

भाजपा शासन में बेटियों का बुरा हाल



प्रतिष्ठित बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के जिन तीन आरोपियों को पुलिस ने घटना के दो माह बाद धर दबोचा है, वे तीनों ही भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के पदाधिकारी निकले। उन्होंने पहली नवम्बर की रात एक छात्रा के साथ बंदूक की नोक पर इस कृत्य को अंजाम दिया था। घटना में उनकी संलिप्ति पाये जाने के बाद भाजपा ने चाहे तीनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया हो, तो भी यह साबित हो जाता है कि पार्टी के साथ काम करने वाले चाहे जितनी चरित्र और जीवन मूल्यों की बात करें, उनकी चाल, चेहरा और चरित्र एकदम विपरीत है। ये तीनों वाराणसी आईटी सेल के पदाधिकारी हैं जिनका काम पार्टी की नीतियों व कायाक्रमों का प्रचार करना होता है। भाजपा के लोगों के जिस प्रकार से अलग-अलग अपराधों में हाथ पाये जा रहे हैं, उससे साफ है कि पार्टी ऐसे लोगों की शरणस्थली बन गई है। लंका पुलिस थाना अधिकारियों के मुताबिक जिन तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम हैं- कुणाल पाडेय, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल। कुमार आईटी सेल का संयोजक है तो सक्षम सह संयोजक। आनंद भी इन दोनों का सहयोगी बताया गया है। घटना की रात बीएचयू महिला छात्रावास की एक छात्रा रात को घूमने निकली तभी तीनों उसके मुंह को दबाकर एक कोने में ले गये। बंदूक दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसका फेन भी उन्होंने छीन लिया और शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी शिनाख्त हुई जो बुलेट पर सवार होकर आये थे। तीनों आरोपियों के सोशल

मैंडिया पर उनके फेटो जिन बड़े लोगों के साथ वायरल हो रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरंगी आदि हैं। वाराणसी मोदी की लोकसभा सीट है। इस नाते देखना यह है कि क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले मोदी इस बाबत क्या करते हैं। ऐसे ही, कोर्ट के जरिये दोष सिद्धि के पूर्व बेहद तत्परता से आरोपियों के घरों, दुकानों यहां तक कि पूरी बस्तियों पर भी बुलडोजर चलाने वाले आदित्यनाथ इन पर वैसे ही कहर बरपाते हैं या नहीं, जैसे कि वे भाजपा विरोधियों पर बरपाते हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि ऐसा कर्तव्य नहीं होगा क्योंकि इस देश में दो तरह के कानून चलते हैं- पहला भाजपा विरोधियों के लिये और दूसरा भाजपा समर्थकों के लिये। विरोधियों के खिलाफ आरोप लगाना ही कार्रवाई के लिये कामी होता है जबकि समर्थकों के दोष सवित हो जाने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी तो दूर, उन्हें बचाये जाने की कोशिशें भी आखिरी दम तक होती हैं। हाथरस, उत्त्राव से लेकर लखीमपुर खीरी तक के मामले बताते हैं कि बलात्कार हो या हत्याएं- भाजपायियों के लिये सब कुछ जायज है। प्रशासन भी उन्हें हाथ लगाने की जुर्त नहीं करता। इस मामले में सम्भवतः आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य बहुत ही मजबूत रहे होंगे इसलिये पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी होगी। अब देखना तो यह है कि क्या कोर्ट में इनके खिलाफ आरोप साबित हो सकेंगे या ये वैसे ही निकल आयेंगे जिस प्रकार से देश में हुए कुछ अन्य मामलों में आरोपी साफ बच निकले हैं। इस वारदात से कई प्रश्न भी खड़े होते हैं। पहली बात तो यह कि योगी बार-बार दावा करते रहे हैं कि उनके प्रदेश में कानून का इतना डर है कि कोई भी महिला गहनों से लदकर आधी रात को अकेली स्कूटी पर धूम सकती है। कोई असामाजिक तत्व उसकी ओर आंखें उठाकर भी नहीं देख सकता। योगी यह भी दावा करते हैं कि अपराधी उनके राज्य से निकल भागे हैं। बीएचयू परिसर तो वैसे भी सुरक्षित माना जाता रहा है क्योंकि उसमें कुलपति का सीधा नियंत्रण होता है। देश भर से बड़ी संख्या में आई लड़कियां यहां पढ़ती हैं। छात्रावासों में कुलपति, अधीक्षकों एवं प्रोफेटरों की बनाई सुरक्षा व्यवस्था में भरोसा कर वे अपना भविष्य बनाने में जुटी रहती हैं। वर्षों से यह व्यवस्था बनी हुई थी, परन्तु देखा यह गया है कि पिछले 8-9 सालों में बीएचयू समेत देश के ज्यादातर श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में सरकार की दखलंदाजी बढ़ी है। भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े कुलपति, कुलसचिव और प्रोफेसर-डीन के हाथों में पूरा प्रशासन आ गया है। साथ ही, इसी विचारधारा के छात्र इन परिसरों का वातावरण दूषित कर रहे हैं। उन्हें पूरा संरक्षण विविध प्रशासन से तो मिलता ही है, स्थानीय पुलिस भी मददगार होती है। पहले बाहरी तत्व परिसरों में मरणशीलता करने की हिमात नहीं कर पाते थे। अब उनका न सिर्फ सीधा प्रवेश हो गया है वरन् उन्हें मनमर्जन व्यवहार करने की भी आजादी है। इससे सिफलड़कियां नहीं बल्कि भाजपा विरोधी विचारधारा का समर्थन करने वाले छात्र-छात्राएं भी असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। पहले ये विश्वविद्यालय वैचारिक विभिन्नता और अलग-अलग विचारों की अभिव्यक्ति के केन्द्र माने जाते थे। अब ऐसा नहीं है। साथ ही, जिस विचारधारा के साथ ये आरोपी संलग्न हैं, वे मत विभिन्नता में विश्वास तो करते ही नहीं, महिलाओं के पद्धने-लिखने, उनकी आजादी व सशक्तिकरण के भी खिलाफ हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि भाजपा शासित राज्य महिला उत्तीर्ण एवं अपराधों के मामलों में कामी ऊपर हैं। इसका कारण यही है कि अपराधी देखते हैं कि किस प्रकार से पार्टी व सरकार अपने से जुड़े लोगों को बचाती है। इससे महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते हैं तो यह स्वाभाविक है।

कम नहीं है समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका

निशा दानु

The image is a composite of two photographs. On the left, there is a portrait of a woman with dark hair, wearing a pink sari with a white border. She is looking slightly to her right. On the right, there is a close-up of another woman's face, focusing on her eye and nose area. This second woman has dark hair and is wearing heavy, colorful makeup in shades of yellow, orange, and red.

A vibrant, multi-colored collage featuring several Indian women's faces. The women are depicted in different styles and colors, some with traditional bindis and sarees. The overall composition is a diverse and colorful representation of Indian femininity.

लालकन दश के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक ताने-बाने में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है। इसकी एक मिसाल पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड का दूरदराज गांव जगथाना है। कपकोट ब्लॉक से करीब 30 किमी और जिला बागेश्वर से करीब 35 किमी दूर यह गांव सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे रहने के साथ-साथ वैचारिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। इस गांव में आज भी महिलाओं को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं है। जहां लड़कों को वंश का उत्तराधिकारी तो लड़कियों को बोझ समझा जाता है। इन क्षेत्रों में महिला समानता से अधिक रुढ़िवादी धारणाएं हावी हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। उसके लिए शिक्षा के विशेष प्रयास किये जाते हैं, जबकि

ड़कियों के सपनों का घर को चारदावारिया
क सीमित कर दिया जाता है। उसे पढ़ाई
रखने के लिए भी स्कूल कम ही भेजा जाता
जबकि लड़कों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान
या जाता है। हालांकि नई पीढ़ी की
शिक्षारियां अब इस सोच पर सवाल उठाने
में आगे नहीं हैं। इस संबंध में गांव की एक 16
वर्षीय किशोरी पूजा प्रश्न करती है कि
अधिकरियर एक महिला को उसके अधिकारों से
चूत क्यों रखा जाता है? लड़कियों को
उन्हें और आगे बढ़ने से क्यों रोका जाता
है? समाज उसे बोझ क्यों समझता है?
बैकिस समाज निमाण में उसकी भूमिका
क्यों से कहीं अधिक होती है? लड़के से
आगे बढ़ने का सपना देखने वाला यही
समाज भूल जाता है कि उस बंश की नींव
औरत ही रखती है। इसके बावजूद

त लड़कियों का बोझ समझता है और उनको खेल में ही मार देना चाहता है? सिर्फ ही नहीं जाति, समुदय और रंग के पार पर भी लड़कियों के साथ भेदभाव जाता है। शिक्षा का मंदिर कहे जाने स्कूल में लड़कियों को प्रोत्साहित करने नगर उसका मनोबल तोड़ा जाता है। इसके बार्थिक समारोह में मंच पर भाषण के लिए शिक्षक लड़कियों से अधिक लड़कों को प्राथमिकता देते हैं। उनकी विचार सोच होती है कि लड़कों की जीवन में लड़कियां बोल नहीं सकती हैं, तो बात नहीं रख सकती हैं। जबकि लड़कों का इसके विपरीत होता है। यदि लड़कों का उत्साहवर्धन किया जाए तो ये आत्मविश्वास के साथ अपनी बात सकती हैं लेकिन घर से लेकर स्कूल

जाग तक उसके मनोबल को केवल हीने के नाम पर तोड़ा जाता है। इस गांव की एक 52 वर्षीय महिला कहती है कि वह लड़कियों के आगे और उनके आत्मनिर्भर बनने की दिलचस्पी, लेकिन किशोरियों के प्रति समाज नीति बातें उनका मनोबल तोड़ देती हैं। चाह कर भी अपनी बेटियों का बढ़ा नहीं पाती हैं। वर्षी 40 वर्षीय नीति कहती है कि सरकार ने लड़कियों का बढ़ने के लिए अवसरों का द्वारा दिया है, लेकिन ग्रामीण समाज की एक सोच लड़कियों को आगे बढ़ने बन जाती है। रेती देवी की बातों परन करते हुए 42 वर्षीय शांति देवी कि ग्रामीण समाज को लगता है कि वर्षों का पढ़-लिख कर आत्मनिर्भर और सही-गलत के फैसले पर उठाना दरअसल उनका सर चढ़ना मानी करना है जो समाज के हित में है। लेकिन यही काम यदि लड़के करें तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होती एक अन्य महिला मालती देवी कि समाज किशोरियों को पढ़ने में भी ज्यादा रुचि नहीं रखता है कि शिक्षा पर खर्च करने के बाद भी इंज में पैसे खर्च होते हैं। ऐसे में वह कोशिक्त करने की जगह गृहस्थी को सीखने पर अधिक जोर देता 38 वर्षीय निर्मला देवी कहती है कि समाज में लड़कियों को शिक्षित आत्मनिर्भर बनने का खाब देखने यादी तो मिल सकती है, लेकिन उसे रखने की छूट नहीं मिलती है। जागरूकता के अभाव में आज भी ग्रामीण समाज किशोरियों के प्रति संकुचित मानसिकता का ही पक्षधर होता है। वह कहती है कि यह किसी एक परिवार या जाति की सोच नहीं बल्कि जगथाना गांव के उच्च हो या निम्न समुदाय, किशोरियों और महिलाओं के प्रति सभी की सोच एक जैसी है। जिसे समाप्त करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पितृसत्तात्मक समाज में किशोरी शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच केवल पुरुषों की है, बल्कि जागरूकता के अभाव में कई महिलाएं भी लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीन नजर आती है। गांव की 48 वर्षीय चंपा देवी कहती है कि आखिर लड़कियों को इतना पढ़ा-लिखा कर क्या करना है? एक दिन तो उहें पराया घर जाकर खाना ही पकाना है। ऐसे में अच्छा है कि हम उनकी शिक्षा पर खर्च करने से अधिक उनकी दहेज पर पैसा खर्च करें। वह जितना अधिक दहेज लेकर जाएंगी, सम्झौता में उनका मान उतना ही बढ़ेगा। दरअसल चंपा देवी की यह सोच किशोरियों के प्रति समाज की नकारात्मक सोच को उजागर करता है। जिसे बदलने की जरूरत है। समाज को इस बात के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है कि सभ्य समाज के निर्माण में लड़कियों की लड़कों के बराबर भूमिका है। इससे न केवल विकास में संतुलन पैदा होता है बल्कि यह महिला हिंसा को भी खत्म करता है। यदि किशोरियों को भी उचित मंच दिया जाए तो वह बखूबी अपनी आवाज बुलंद कर सकती है। इसका उदाहरण शहरी क्षेत्र है जहां किशोरियां विकास के हर क्षेत्र में बराबर का योगदान दे रही हैं।

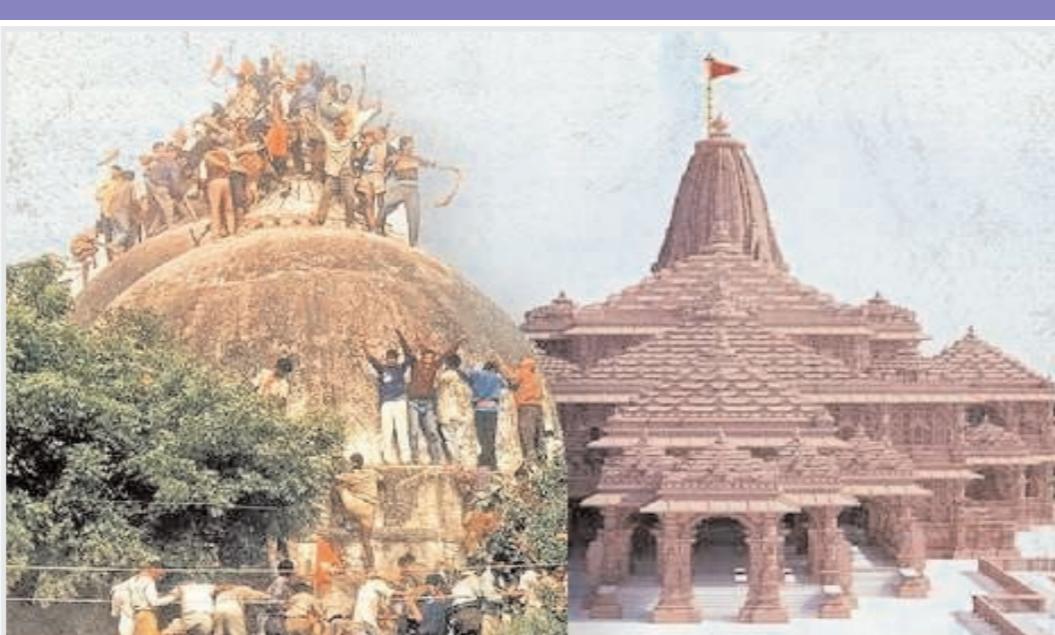
नव् वर्ष का पृथ्वी के लिए नया संकल्प जल संरक्षण एक मात्र विकल्प

संजीव ठाकुर

बाबरी धूंस से राममंदिरः भारतीय राजनीति की बदलती दशा और दिशा

2

यह वह समय है जब हमें नेहरु के आधुनिक भारत के मंदिरों की संकल्पना और वैज्ञानिक समझ के विस्तार और विकास के प्रयासों को याद करना चाहिए। इस समय धर्मिकता और अंधश्रद्धा को जबरदस्त बढ़ावा दिया जा रहा है। जब हमने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को तोड़ा था, तब हमने यह संकल्प लिया था कि अंतिम पर्कि का अंतिम व्यक्ति हमारा फेकस होगा। परन्तु आज राजनीति अयोध्या के राममंदिर के आसपास धूम रही है। अधीन होने के बाद भारत ने जो दिशा और राह चुनी, उसकी रूपरेखा जवाहरलाल नेहरु के ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण में थी। नेहरु ने कहा, भारत की सेवा का अर्थ है लाखों-लाख पीड़ितों की सेवा। भारत की सेवा का अर्थ है निर्धनता, अज्ञानता, रोग और अवसर की असमानता को समाप्त करना... हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की अभिलाषा तो यही है कि हर अंचुल से हर आसू पोछ जाए। यह हमारे बस की बात न भी हो, तब भी, जब तक आंसू हैं और पीड़ि हैं, हमारा काम खत्म नहीं होगा। और इसी सन्दर्भ में उहोने भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते हुए अपने भाषण में आधुनिक भारत के मंदिरों की बात कही। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने लिखा, अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में प्रधानमंत्री



मंदिर खोजे जाने लगे। बाबरी मस्जिद को लेकर खड़ा किया गया विवाद, इसी अभियान का हिस्सा था। सन् 1980 में संघ परिवार में एक नए सदस्य का जन्म हुआ। वह सदस्य थी भाजपा। कुछ दिन तक यह नई पार्टी गांधीवादी समाजवाद में आस्था रखने का नाटक करती रही। इसका नेतृत्व नर्म नेता का मुखौटा पहने अटलबिहारी वाजपेयी की हाथ में था। वाजपेयी संघ की विचारधारा में पूर्ण आस्था रखते थे। हिन्दू तन मन, हिन्दू जीवन, उहोने अपने बारे में लिखा था। लेकिन उहोने बड़ी सफाई से अपने असली हिन्दू राष्ट्रवादी चेहरे को ढंक कर रखा। बाद में उनकी जगह लालकर्ण आडवाणी ने ले ली। आडवाणी ने मंदिर बही बनाए को नारा बुलंद किया। संघ परिवार लोगों को यह समझाने में सफल रहा कि भगवान राम का जन्म ठीक उसी स्थान पर हुआ था जहां बाबरी मस्जिद थी। मंडल आयोग की रपट के लागू होने से राम रथयात्रा को और ताकत मिली। यात्रा अपने पीछे खून की एक गहरी रेखा छोड़ती गई। सन् 1990 के आसपास, देश के विभिन्न हिस्सों में इस यात्रा के गुजरने के बाद हुई हिंसा में करीब 1,800 लोग मारे गए। लालप्रसाद यादव द्वारा आडवाणी की गिरफ्तारी के साथ यह यात्रा समाप्त हो गई। मस्जिद की पूरी जमीन हिन्दू पक्ष को दी। अपनी इस सफलता से आलहादित संघ परिवार ने देश से और विदेशों से भी भारी धनराशि एकत्र की और उससे बना भव्य राममंदिर अब तैयार है। इसका उद्घाटन पूरे मुसलमान, समाज के हाशिये पर धकेल दिए गए हैं। उहें दूसरे दर्जे का नागरिक करेंगे। औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष सरकार के मुखिया के हाथों यह मंदिर जनता के लिए खुलेगा। जब तक बाबरी मस्जिद थी, तब तक वह भाजपा के चुनाव सरकार ने हमारे सविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के मूल्य के भविष्य और उसकी विरासत को किरच-किरच कर दिया है। अपने मोहकों में सिमटे मुसलमान, समाज के हाशिये पर धकेल दिए गए हैं। उहें दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। मंदिर के उद्घाटन के मौके का इस्तेमाल हिन्दुओं को गोलबंद करने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका और अन्य देशों में अप्रवासी भारतीय इससे और अब मंदिर के उद्घाटन का उपयोग ध्वनीकरण को और गहरा करने और उससे चुनावों में लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। लोगों को अयोध्या ले जाने के लिए बड़ी संख्या में विशेष रेलगाड़ियों और बसों का इंतजाम हो रहा है। यह वह समय है जब हमें नेहरू के आधुनिक भारत के मौदिरों की संकल्पना और वैज्ञानिक समझ के विस्तार और विकास के प्रयासों को याद करना चाहिए।

सन् 1992 के छह दिसंबर को चुने हुए कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को जर्मीदाज कर दिया। उन्हें बाकायदा इसका प्रशिक्षण दिया गया था और उन्होंने इसकी रिहर्सल भी की थी। जिस समय मस्जिद तोड़ी जा रही थी, मंच पर आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती भी थे। मंच से एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दे और ये तो केवल झांकी है, काशी, मथुरा बाकी है-जैसे नारे लगाए जा रहे थे। बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद मुंबई, भोपाल, सूरत और कई अन्य शहरों में भयावह सांप्रदायिक हिंसा हुई। और अंततः हमारी न्याय प्रणाली ने हिन्दू राष्ट्रवादी ताकतों के समक्ष समर्पण करते हुए इस मामले का निर्णय आस्था के आधार पर सुना दिया। फैसले में उन लोगों के नाम लिए गए जिन्होंने मस्जिद के ध्वंस का नेतृत्व किया था मगर उन्हें उनके अपराध की कोई सजा नहीं दी गई। न्यायपालिका ने मस्जिद की पूरी जमीन हिन्दू पक्ष को दे दी। अपनी इस सफलता से आल्हादित संघ परिवार ने देश से और बिदेशों से भी भारी धनराशि एकत्र की और उससे बना भव्य रामर्मादर अब तैयार है। इसका उद्घाटन पूरे हिन्दू कर्मकांडों के साथ स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे। औपचारिक रूप से धर्मराजपेरेश्व सरकार के मुखिया के हाथों यह मंदिर जनता के लिए खुलेगा। जब तक बाबरी मस्जिद थी, तब तक वह भाजपा के चुनाव

अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। उसके बाद से भव्य राममंदिर का निर्माण पार्टी के चुनाव घोषणापत्रों और वायदों का अहम हिस्सा रहा है। गुजरे सालों में मुसलमान अपने मोहल्लों में सिमट गए हैं, देश का सांप्रदायिक आधार पर ध्वनीकरण हुआ है और भाजपा की चुनावी ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई है। वर्तमान स्थिति का सारांगधर्मित वर्णन लेखक ए.एम. सिंह ने इन शब्दों में किया है सत्ता में अपने के बाद से, भाजपा के राजनीतिक आख्यान ने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया है। और भाजपा सरकार ने इसी दिशा में कई कदम भी उठाए हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पारित किया किया... भारत की नागरिकता को हिंदुत्व के सिद्धांतों के आधार पर पुनर्निर्भाषित कर, भाजपा सरकार ने हमारे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के मूल्य के भविष्य और उसकी विरासत को किरच-किरच कर दिया है। अपने मोहल्लों में सिमटे मुसलमान, समाज के हाशिये पर धकेल दिए गए हैं। उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। मंदिर के उद्घाटन के मौके का इस्तेमाल हिन्दुओं को गोलबद्द करने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका और अन्य देशों में अप्रवासी भारतीय इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। देश के भीतर, आरएसएस और उसके परिवार के सदस्य हिन्दुओं को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि या तो वे नए मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में जाएं या उस दिन स्थानीय मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना करें। इस समारोह में किसे आमंत्रित किया गया है और किसे नहीं, इसको लेकर भी कुछ विवाद सामने आये हैं। पहले मंदिर ट्रस्ट ने बाबरी मस्जिद के ध्वंस के मूल्य आर्किटेक्ट अडवाणी और उनके नजदीकी सहयोगी मुरली मोहर जोशी से कहा कि-इन दोनों नेताओं की उम्र और अयोध्या में उस समय जबरदस्त ठण्ड पड़ने की सम्भावना के चलते उन्हें कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए। बाद में शायद इस मसले पर पुनर्विचार हुआ और विहिप ने दोनों को आमंत्रित किया। बाबरी मस्जिद के ध्वंस ने पिकापरस्त ताकतों को सत्तासीन किया और अब मंदिर के उद्घाटन का उपयोग ध्वनीकरण को और गहरा करने और उससे चुनावों में लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। लोगों को अयोध्या ले जाने के लिए बड़ी संख्या में विशेष रेलगाड़ियों और बसों का इंतजाम हो रहा है। यह वह समय है जब हमें नेहरू के आधुनिक भारत के मंदिरों की संकल्पना और वैज्ञानिक समझ के विस्तार और विकास के प्रयासों को याद करना चाहिए।

